by the present managing Director of the Company. The allegations regarding Tax evasion have been brought to the notice of Income Tax Authorities for such action as is considered appropriate by them, and they are seized of the same. As regards transfer of shares, the dispute is subject of a civil suit in the court concerned in Hyderabad and the matter is subjudice. Further action as per Companies Act, 1956, will be considered if any specific violations of the provisions of the Act come to notice. As regards protection of interests of shareholders, it is open to the aggrieved members to file applications in the prescribed menner to the Company Law Board for, relief if admissible, as per procedures in sections 397/398 of the Companies Act.

British Court Judgement for making payment to British solicitors firm

3290. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of LOW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a British Court has in a judgement, asked the Government and certain Government departments to pay over rupees one crore to a solicitors, firm in London for the litigation pursued by Government agencies in U. K;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) to (c) In a case filed by one of the Solicitors in the panel maintaned by the High Commissioner of India at London, an *ex-parte* judgement was passed by a British Court. The Judgement has been set-aside with certain conditions and the matter is sub-judice.

उत्तर प्रदेश में लंबित अदालती मामले

3291. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर अदालती मामले भूमि से संबंधित होते है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय चल रहे अदालती मामलों का जिलावार ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने मामले भूमि से संबंधित है ; और

(ग) सरकार भूमि से संबंधित अदालती मामलों को तीन महीने के भीतर निपटाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार, लंबित मामलों का जिलावार और विषयवार ब्यौरा नहीं रखती है । तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-12-1990 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 535985 मामले लंबित थे । इनमें से, 18763 मामले भूमि सुधार और अधिकतम भूमि सीमा से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश में 30-6-1990 को सभी जिला अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 18,93,514 थी । इनमे से, 6365 मामले भूमि अर्जन से संबंधित थे।

(ग) किसी भी विशेष प्रकार के मामले के निपटारे के लिए, विशिष्ट समय सीमा विहित करना संभव नहीं । तथापि, सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए है । इसके अतिरिक्त न्यायालय, विधि के सामान्य प्रश्न वाले मामले को एक समूह